अध्याय II: राजस्व और विवरणी दाखिला की प्रवृति

इस अध्याय में भारत सरकार के जीएसटी राजस्व, आईजीएसटी का लेखांकन और विवरणी दाखिला की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है।

2.1 राजस्व प्रवृत्ति

2.1.1 भारत सरकार के समग्र संसाधन

संघ सरकार के कर राजस्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्ति शामिल थी। जीएसटी से पूर्व, अप्रत्यक्ष करों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क शामिल थे। जीएसटी के लागू होने के बाद, पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को जीएसटी से बदल दिया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता रहा और तम्बाकू को जीएसटी के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन किया गया। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए संघ सरकार का समग्र कर राजस्व नीचे दी गई तालिका संख्या 2 में दिया गया है:-

तालिका संख्या 2: भारत सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

कर घटक	**2016-17 (जीएसटी पूर्व)**	**2017-18 (जीएसटी के बाद)**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	22,23,988	23,64,148
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	8,49,801	10,02,738
ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	8,66,167	9,16,445
iii. गैर-कर प्राप्तियां	5,06,721	4,41,383
iv. अनुदान-सहायता और योगदान	1,299	3,582
ख. विविध पूंजी प्राप्तियां	47,743	1,00,049
ग. ऋणों की वसूली और अग्रिम	40,971	70,639
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	61,34,137	65,54,002
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**84,46,839**	**90,88,838**

स्रोत: संबंधित वर्षों के केंद्रीय वित्त लेखा।

2016-17 से 2017-18 में संघ सरकार की समग्र प्राप्तियों में ₹ 6,41,999 करोड़ की वृद्धि हुई। कुल राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी 2016-17 में 38.95 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 38.76 प्रतिशत के साथ लगभग स्थिर बनी हुई है। अप्रत्यक्ष करों में 2016-17 से 2017-18 में

5.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि 2016-17 के दौरान यह वृद्धि दर 21.33 प्रतिशत थी। जीएसटी राजस्व के विवरण पर आगामी पैराओं में चर्चा की गई है।

2.1.2 भारत सरकार का जीएसटी राजस्व: बजट अनुमान बनाम वास्तविक प्राप्ति

बजट अनुमानों और वास्तविक जीएसटी प्राप्तियों की एक तुलना नीचे तालिका सं. 3 में दर्शायी गई है।

तालिका संख्या 3: बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्ति (जीएसटी)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान (बीई)			संशोधित अनुमान (आरई)			वास्तविक		
	सीजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर	सीजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर	सीजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर
2017-18	कोई बीई नहीं केवल आरई			2,21,400	1,61,900	61,331	2,03,261	1,76,688*	62,612
2018-19	6,03,900	50,000	90,000	5,03,900	50,000	90,000	4,57,535#	28,947#	95081#

स्त्रोत: संघ वित्त लेखाओं और संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेजों की प्राप्ति

* राज्यों को ₹ 67,998 करोड़ सौंपे और शेष ₹ 1,08,690 करोड़ केन्द्र द्वारा रखे गये

मार्च 2019 के अनंतिम आंकडे जो सीजीए वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जैसा कि ऊपर तालिका 3 से देखा जा सकता है, सीजीएसटी राजस्व अनुमानों से कम था और 2018-19 के अनंतिम आंकडे भी संकेत देते है कि सीजीएसटी राजस्व आरई के लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं जो सीजीएसटी के मूल बीई की तुलना में ₹ एक लाख करोड़ कम है। आईजीएसटी के विवरणों की आगामी पैराओं में चर्चा की गई है।

2.1.3 आईजीएसटी का लेखाकंन और संव्यवहार

आईजीएसटी, अंतर-राज्यीय आपूर्ति और वस्तुओं और सेवाओं के आयात / निर्यात पर उद्ग्रहित किया जाता है और भारत सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है जैसा कि आईजीएसटी अधिनियम में निर्दिष्ट है; संघ और राज्यों के बीच बांटा जाता है। आईजीएसटी को शुरू में भारत के समेकित निधि में मुख्य शीर्ष मुख्य शीर्ष 0008 के तहत एकत्र किया गया और फिर एक बार जब करदाता इसे आगे की आपूर्ति पर सीजीएसटी / एसजीएसटी / यूटीजीएसटी का भुगतान करने के लिए आईटीसी के रूप में उपयोग करता है (यहाँ आईटीसी क्रॉस उपयोग के रूप में संदर्भित किया गया है), सीएफआई या संबंधित राज्य सरकार के एसजीएसटी शीर्ष के अंतर्गत सीजीएसटी/जीएसटी से प्रासंगिक

खाताशीर्ष अर्थात सीजीएसटी/यूटीजीएसटी में राशि हस्तांतरित की जाती है। इसके अलावा, जब किसी कारण से आगे के उपयोग के लिए आईजीएसटी का आईटीसी अयोग्य हो जाता है या व्यपगत हो जाता है (आईटीसी श्रृंखला को टुटना), तो संघ और राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। आईटीसी प्रति उपयोगिता और विनियोग राशि हर महीने एक एल्गोरिथम का उपयोग करके प्राप्त की जाती है जो जीएसटी पोर्टल पर दाखिल विवरणी के आधार पर चलती है।

आईजीएसटी के लिए लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, आईजीएसटी के तहत संग्रहण मुख्य शीर्ष 0008 के तहत बुक किए जाने हैं, जिसमें सामानों और सेवाओं के आयात / निर्यात पर आईजीएसटी की बुकिंग के लिए उप मुख्य शीर्ष '01' और सामानों और सेवाओं की घरेलु आपूर्ति पर आईजीएसटी के लिए '02' हैं। आईटीसी प्रति उपयोगिता के साथ-साथ सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को अलग-अलग आईजीएसटी के विभाजन को इन शीर्षों के अंतर्गत रखकर लघु शीर्ष उपलब्ध कराये गये हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए केंद्र सरकार के वित्त खातों में मुख्य शीर्ष 0008 के अंतर्गत बुक की गई प्रविष्टियों की सूची नीचे तालिका 4 में दी गई है:-

तालिका संख्या 4: मुख्य शीर्ष 0008 आईजीएसटी के तहत बुकिंग

(₹ करोड़ में)

विवरण	**0008-01 माल के आयात / निर्यात और सेवाओं पर आईजीएसटी**	**0008-02 वस्तुओं और सेवाओं की घरेलु आपूर्ति पर आईजीएसटी**	**कुल**
साल के दौरान संग्रहण	2,02,141	1,80,485	**3,82,626**
आईटीसी प्रति उपयोगिता	शून्य	(-)1,45,350	**(-)1,45,350***
आईजीएसटी का विभाजन	शून्य	(-)25,587	**(-)25,587***
निपटान और विभाजन के बाद शेष	2,02,141	9,547	**2,11,688**
अग्रिम विभाजन	शून्य	(-)35,000	**(-) 35,000**
अग्रिम विभाजन के बाद शेष	2,02,141	(-) 25,453	**1,76,688**
राज्यों को सौंपा गया हिस्सा (अंतरण)	(-) 67,998	शून्य	**(-)67,998**
	1,34,143	(-)25,453	**1,08,690**

*इस प्रतिवेदन के अध्याय III में रिपोर्ट किया गया है कि आईजीएसटी निपटान/ प्रभाजन एल्गोरिथम की अशुद्धता और कमियों के तहत आईजीएसटी

निपटान और प्रभाजन की सटीकता को जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के भाग के रूप में पहचान की गई है।

जैसा कि तालिका सं. 4 से देखा जा सकता है, उप मुख्य शीर्ष 02 (घरेलु सामान और सेवाओं की आपूर्ति पर आईजीएसटी) के अंतर्गत ₹ 1,80485 करोड़ के संग्रहण के प्रति ₹ 1,45,350 करोड़ और इन समायोजनों के बाद ₹ 9,547 करोड़ शेष छोड़ते हुए विभाजन के प्रति ₹ 25,587 आईटीसी प्रति उपयोगिता के संबंध में आईजीएसटी से बाहर हस्तांतरित किये गये।

उप-मुख्य शीर्ष 01 (माल और सेवाओं के आयात निर्यात) पर आईजीएसटी) से विभाजन या आईटीसी प्रति उपयोग के लिए कोई समायोजन नहीं किये गये थे हालांकि वर्ष के दौरान ₹ 2,02,141 करोड़ की राशि एकत्र की गई थी। आयात और प्रतिदाय के डेटा के गैर-उपयोग के कारण आईजीएसटी एल्गोरिथ्म में कमियों पर जीएसटी इस रिपोर्ट के अध्याय III के (भाग सी का संदर्भ ले) की आईटी लेखापरीक्षा पर हमारी टिप्पणियों के भाग के रूप में टिप्पणी की गई है।

आईजीएसटी में काफी शेष के कारण, जीएसटी परिषद ने जनवरी 2018 में आयोजित 25वीं बैठक में केंद्र और राज्यों को अनंतिम आधार पर 35,000 करोड़ रुपये के अग्रिम निपटान की सिफारिश की। इस अग्रिम का निपटान को आधार के रूप में जीएसटी में शामिल करों से राज्यों के राजस्व 2015-16 में लेते हुए किया गया था और 2018-19 में राज्यों के बकाया नियमित निपटान के प्रति दस बराबर किश्तों में समायोजित करने का प्रस्ताव किया गया था।

इस अग्रिम निपटान के बाद वर्ष के अंत में आईजीएसटी में ₹ 1,76,688 करोड़ शेष था। भारत सरकार ने केंद्रीय करों के अंतरण के लिए वित्त आयोग सूत्र अपनाते हुए राज्यों / संघशासित प्रदेशों को आईजीएसटी के तहत ₹ 67,998 करोड़ सौंपे। ***आईजीएसटी का अंतरण भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले करों और कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 269 (ए) (अर्थात आईजीएसटी) के तहत लगाए गए शुल्कों को से संविधान के अनुच्छेद 270 (1) में शामिल नहीं किया जाता है।*** जब मंत्रालय ने आईजीएसटी की लेखांकन प्रक्रिया को सीएजी के पास अनुमोदन के लिए भेजा, तो जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित केंद्र और राज्यों की आईजीएसटी की अग्रिम प्रभाजन के लिए प्रक्रिया को सीएजी द्वारा सहमती दी गई थी। लेकिन सीएजी द्वारा विचलन की प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त नहीं की गई थी कि आईजीएसटी का विचलन भारत के संविधान के प्रावधानों के विरूद्ध था।

इसके अलावा, वित्त आयोग के सूत्र का उपयोग करने वाले फंडों के अंतरण का प्रभाव राज्यों के बीच आईजीएसटी फंडों के वितरण पर भी पड़ता है, जो उस अनुपात से काफी भिन्न स्वरूप में जिसमें निधि सामान्य रूप से राज्यों में चले जाती थी, क्योंकि आईटीसी प्रति-उपयोगिता या विभाजन आपूर्ति अवधारणा पर आधारित होती है।

जब हमने (अप्रैल 2019) में यह बताया और वित्त मंत्रालय ने सूचित (मई 2019) किया कि 2017-18 में आईजीएसटी का विचलन किया गया था, तो कानून और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग से औपचारिक राय लेने के बाद, आईजीएसटी शेष के लेखांकन के लिए लंबित लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था। यह आगे कहा गया कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49(5) को संशोधित (अगस्त 2018) किया गया, जो प्रावधान करती है कि आईजीएसटी की आईटीसी का पहले उपयोग हो और तब केवल सीजीएसटी/ एसजीएसटी का भुगतान सीजीएसटी और एसजीएसटी को आईटीसी का उपयोग करे। आईजीएसटी के तेजी से निपटारें को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि 2018-19 के दौरान शेष आईजीएसटी के रूप में विकसित नहीं किया गया है जैसा कि 2017-18 में किया गया था और नियमित निपटान के बाद आईजीएसटी शेष उपलब्ध है और प्रतिदाय को अनंतिम रूप से लागू किया जा रहा है।

वर्ष 2017-18 के दौरान अवक्रमित आईजीएसटी राशि के अधिकार को स्थापित करने के लिए इसके द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई के पहलू पर मंत्रालय का जवाब मौन है। आईजीएसटी अधिनियम की धारा 49(5) में संशोधन जैसे कदम आईजीएसटी के तेजी से उपयोग का प्रावधान करती है और 2018-19 के दौरान आईजीएसटी शेष के अनंतिम निपटान केवल 2018-19 में आईजीएसटी के निपटान को प्रभावित करेगा। आईजीएसटी शेष के वितरण के लिए वित्त आयोग के सूत्र को अपनाने के कारण राज्य के राजस्वों पर प्रभाव के पहलू पर मंत्रालय का जवाब भी मौन था।

यहां पर उल्लेख करना उचित होगा कि 12 फरवरी 2019 को संसद के पटल पर रखी गई संघ सरकार के लेखा (2019 की रिपोर्ट सं. 2) पर सीएजी की रिपोर्ट में, यह सलाह दी गई थी कि भारत सरकार को अपने हिस्से का सही तरीके से लेखा रखना चाहिए और केन्द्रीय हिस्से से ही विचलन होना चाहिए और जीएसटी अधिनियम के अनुसार राज्यों को शेष 50 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। इसे देखते हुए, केन्द्र के व्यय के रूप में परिणामी समायोजन की विधिवत बुकिंग के लिए आईजीएसटी के राज्यों की हिस्सेदारी को ठीक से लेखांकित करना चाहिए।

2.1.4 वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर राजस्व की तुलना

भारत सरकार के अप्रत्यक्ष कर संग्रहणों की तुलना माल और सेवाओं पर जीएसटी पूर्व और बाद में करने के लिए, जैसा कि नीचे दी गई तालिका संख्या 6 में दिखाया गया है, हमने राजस्व जीएसटी में शामिल केंद्रीय करों के सभी घटकों से संबंधित माना है।

- 2016-17 के लिए: 2016-17 के सीवीडी और एसएडी के केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क के शामिल किए गए घटक और
- 2017-18 के लिए: 2017-18 की प्रथम तिमाही में संग्रहित करों के अतिरिक्त 2017-18 हेतु वर्ष अंत में आईजीएसटी शेष में सीजीएसटी, यूटीजीएसअी और केंद्र के हिस्से के साथ-साथ 2017-18 की शेष अवधि के दौरान शामिल करों से संबंधित बकाया का संग्रहण शामिल है। राज्यों को विचलन के बाद केन्द्र द्वारा प्रतिधारित आईजीएसटी का शेष हिस्सा है।

मार्च के लिए जीएसटी राजस्व अप्रैल में देय था, जबकि मार्च का राजस्व केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के मामले में भी मार्च में ही देय था। इसलिए अप्रत्यक्ष करों की राजस्व वृद्धि की एक उचित तुलना के लिए, हमने अप्रैल 2018 में एकत्र किए गए केंद्र के मार्च 2018 जीएसटी राजस्व को भी माना है जैसा कि नीचे दी गई तालिका सं. 5 के कॉलम 4 में दिखाया गया है:

तालिका संख्या 5: वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर राजस्व की तुलना

(₹ करोड़ में)

	वर्ष		
कर घटक	**2016-17**	**2017-18**	**2017-18***
पेट्रोलियम और तंबाकू के अलावा अन्य सामान पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,16,901	9,034	9,034
सेवा कर	2,54,499	81,229	81,229
केंद्रीय जीएसटी कर (सीजीएसटी और यूटीजीएसटी)	0	2,04,896	2,37,075
आईजीएसटी**	0	1,08,690	1,08,690
सीवीडी और एसएडी का सीमा शुल्क	1,51,927	43,092	43,092
केंद्रीय विक्रय कर	495	102	102
शामिल मद राजस्व	5,23,822	4,47,043	4,79,222
18-19 के पहले 17-18 में जीएसटी शामिल मदों हेतु राजस्व अंतर		-76,779	-44,600
18-19 से 17-18 में जीएसटी शामिल मदों हेतु राजस्व अंतर (प्रतिशत)		-15	-10

* मार्च 2018 जीएसटी जो अप्रैल 2018 में एकत्र किया गया

** केंद्र द्वारा रखी गई वर्ष के अंत में शेष राशि, जैसा कि पैरा 1.7.4 में व्याख्या की गई

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, जीएसटी के लागू करने के बाद, माल और सेवाओं पर राजस्व (पेट्रोलियम और तंबाकू पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का छोड़कर) 2016-17 में शामिल करों के राजस्व की तुलना में 2017-18 में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल 2018 में एकत्रित सीजीएसटी के मार्च 2018 के राजस्व जोड़ने के बाद भी, राजस्व में 10 प्रतिशत की सीमा तक गिरावट रही है। क्या राजस्व में इस तरह की गिरावट के कारण, के विश्लेषण किए गए और विश्लिषण के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई पर मंत्रालय से उत्तर मांगा गया और उत्तर प्रतीक्षित था।

2.1.5 लोक लेखों में क्षतिपूर्ति उपकर का लघु अंतरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के प्रावधानों जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम और भारत के सीएजी द्वारा समहति पर क्षतिपूर्ति उपकर के लिए लेखांकन प्रक्रिया, के अनुसार, मुआवजा उपकर लोक लेखों में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। हालाँकि, वित्त लेखा 2017-18 से, यह देखा गया कि लोक लेखों के मुआवजा उपकर के ₹ 6,466 करोड़ के कम स्थानांतरण किये। इस के अतिरिक्त देखा गया कि सहमत लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को मुख्य शीर्ष 2047-अन्य राजकोषीय सेवाओं, लघु शीर्ष 797-आरक्षित निधि में डेबिट के स्थानांतरण करके लोक लेखों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हालाँकि, वित्त लेखा 2017-18 के अनुसार, मुख्य शीर्ष 2047 में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई थी।

मंत्रालय की ओर से (फरवरी 2019) के लिए इन कारणों का उत्तर नहीं दिया गया था और उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

2.1.6 संक्रमणकालीन क्रेडिट, प्रतिदाय और संग्रहण लागत

(ए) संक्रमणकालीन क्रेडिटस, (बी) करदाताओं द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय, संसाधित और लंबित और (सी) संग्रह की लागत के आंकडें मंत्रालय द्वारा प्रदान नहीं किये गये हैं। इसलिए हम इसका विश्लेषण नहीं कर पाए और इस रिपोर्ट में शामिल हैं।

2.2 जीएसटी पंजीकरण

2.2.1 पैन-इंडिया जीएसटी पंजीकरण

जीएसटी के तहत श्रेणी-वार पंजीकरण नीचे तालिका 6 में दिए गए हैं:-

तालिका संख्या 6: पंजीकरण का विवरण

पंजीकर्ता की श्रेणी	पंजीकर्ता की संख्या	कुल का प्रतिशत
सामान्य करदाता	1,00,49,983	84.05
कम्पोजिशन करदाता	17,48,885	14.63
स्रोत पर कर कटौतीकर्ता	1,40,930	1.18
स्रोत पर टैक्ट संग्रहणकर्ता	5,500	0.05
इनपुट सेवा वितरक	8,885	0.06
अन्य (आकस्मिक, एनआरटीपी, ओआईडीएआर)	1,741	0.01
कुल पंजीकरण	**1,19,55,924**	

स्रोत: जीएसटीएन दैनिक सारांश रिपोर्ट

28 फरवरी 2019 को जीएसटी के तहत कुल पंजीकरण 1.20 करोड़ थे, जिनमें से सामान्य करदाताओं का 84.05 प्रतिशत और कंपोजिशन करदाताओं का लगभग 14.63 प्रतिशत था। 59,74,885 को पूर्व-जीएसटी शासन से विस्थापित किया गया था, कुल पंजीकरण लेखांकन लगभग 50 प्रतिशत थे जबकि शेष नए पंजीकरण थे।

निम्नलिखित चार्ट सं. 5 में इन दो श्रेणियों के तहत 90 प्रतिशत पंजीकरण करते हुए हैं शीर्ष 16 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (यूटीज) में सामान्य करदाताओं और कम्पोजिशन डीलरों के वितरण को दर्शाया गया है:-

चार्ट सं. 5: सामान्य बनाम कम्पोजिशन करदाता

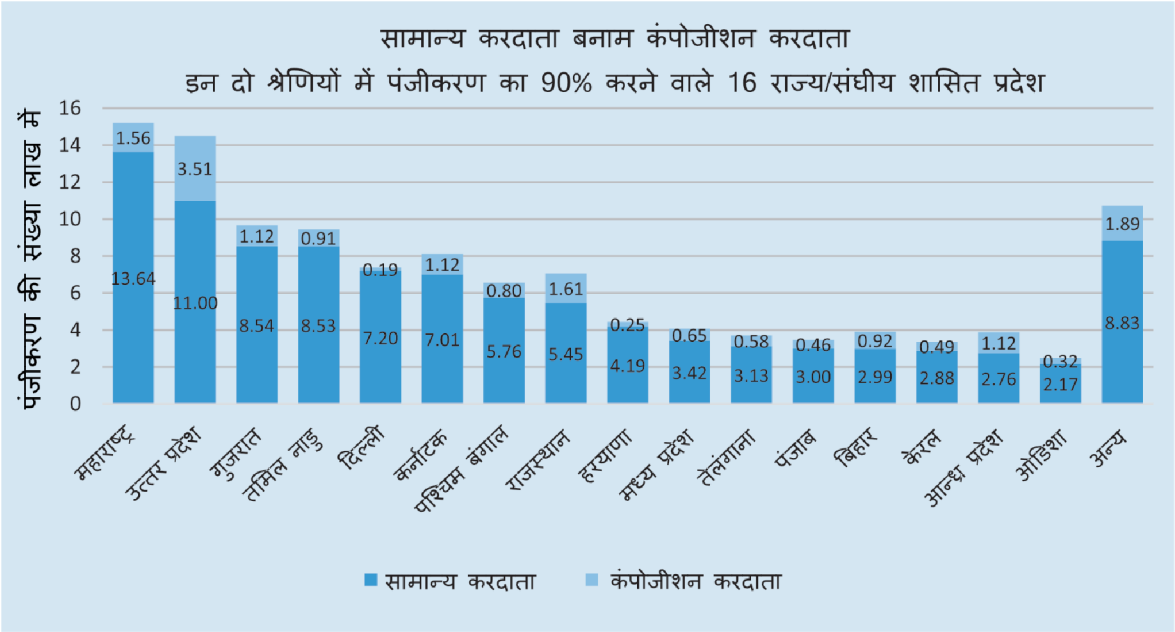

स्रोत: 28 फरवरी 2019 को जीएसटीएन रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त सांख्यिकीय डेटा।

2.2.2 सामान्य करदाताओं का वितरण

लेखाचित्र सं. 1: सामान्य करदाताओं का वितरण

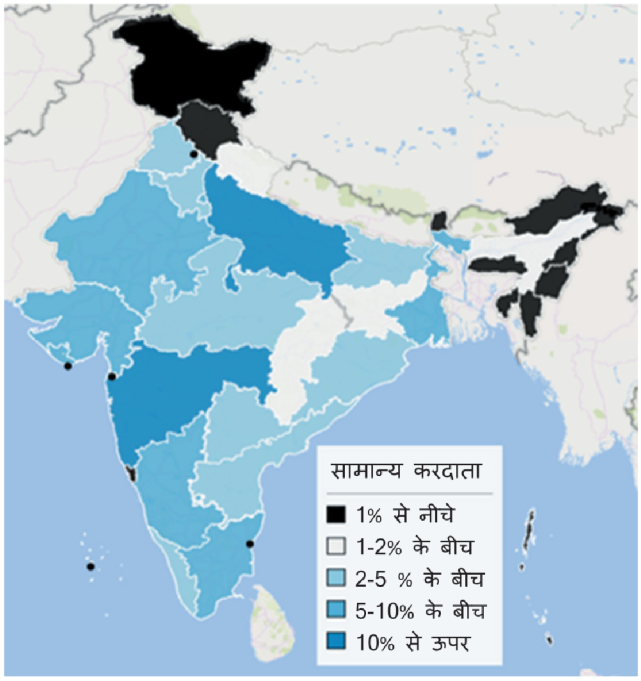

स्रोत: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीएन रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त सांख्यिकीय डेटा

28 फरवरी 2019 तक पूरे भारत में सामान्य करदाताओं के वितरण। चित्र ग्राफ सं. 1 (**परिशिष्ट-III** में सांख्यिकीय जानकारी) में चित्रित किया गया है।

सामान्य करदाताओं की श्रेणी में, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 10 प्रतिशत से अधिक की श्रेणी में आने वाले शीर्ष राज्यों में शामिल थे और इन दोनों राज्यों का देश में कुल करदाता पंजीकरण का 24.51 प्रतिशत था। सोलह राज्य / संघ राज्य क्षेत्र एक प्रतिशत से कम पंजीकरण श्रेणी में थे।

2.2.3 कंपोजिशन कर दाताओं का वितरण

लेखाचित्र सं. 2: कंपोजिशन कर दाताओं का वितरण

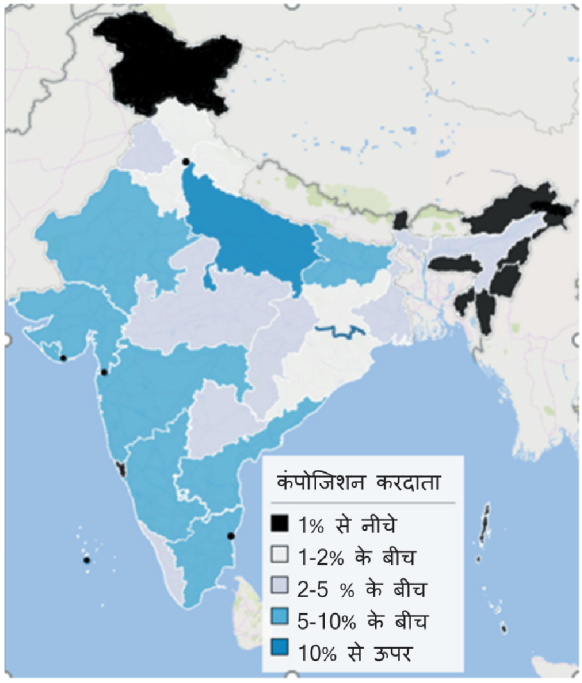

स्रोत: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीन रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त सांख्यिकीय डेटा

कंपोजिशन करदाताओं का वितरण, जिन्होंने 28 फरवरी 2019 तक पूरे भारत में कंपोजीशन लेवी का विकल्प चुना को सचित्र लेखाचित्र सं. 2 में (परिशिष्ट-III में सांख्यिकीय जानकारी) में चित्रित किया गया था।

उत्तर प्रदेश में कुल कम्पोजिशन करदाताओं का 20 प्रतिशत हिस्सा है, और इसके बाद राजस्थान (9.2 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (8.9 प्रतिशत) हैं। पंद्रह राज्य / संघ राज्य क्षेत्र एक प्रतिशत से कम श्रेणी में आते हैं।

2.3 जीएसटी विवरणी दाखिला करने का तरीका

2.3.1 जीएसटीआर-1 और 3 बी का दाखिला तरीका

अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 की अवधि हेतु 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीआर-1 और 3बी को दाखिला करने की प्रवृत्ति, जैसा कि जीएसटीएन द्वारा साझा की गई सारांश रिपोर्ट से संकलित की गई है, को तालिका सं. 7 में दर्शाया गया है:-

तालिका सं. 7: जीएसटीआर-1 और 3बी का दाखिला पैटर्न

विवरणी प्रकार	जीएसटीआर-1			जीएसटीआर-3बी				
महीने	दाखिला हेतु देय	दाखिला की गई रिटर्नें	विवरणी दाखिला करने का प्रतिशत	दाखिला हेतु देय	28 फरवरी तक दाखिला की गई विवरणी	विवरणी दाखिला करने का प्रतिशत	नियत तिथि से दाखिला की गई विवरणी	नियत तिथि से दाखिला करने का प्रतिशत
अप्रैल 18	44,96,316	27,28,772	61	88,17,798	76,94,460	87	56,38,813	64
मई 18	46,82,345	27,48,617	59	91,22,309	78,18,233	86	56,18,925	62
जून 18	93,16,710	70,48,521	76	93,16,710	78,97,701	85	58,39,034	63
जुलाई 18	47,75,626	27,50,521	58	94,70,282	79,57,565	84	64,39,259	68
अगस्त 18	47,26,891	27,28,177	58	96,15,273	80,14,906	83	57,02,349	59
सितम्बर 18	96,57,239	69,98,553	72	96,57,239	80,41,279	83	64,19,403	66
अक्टूबर 18	46,09,444	26,53,997	58	97,57,664	80,52,558	83	59,28,822	61
नवम्बर 18	45,72,118	25,83,371	57	98,46,645	79,13,241	80	63,36,787	64
दिसम्बर 18	99,01,997	64,36,328	65	99,01,997	78,18,108	79	62,49,078	63

अप्रैल 2018 के लिए जीएसटीआर-3बी का दाखिला 87 प्रतिशत था जबकि दिसम्बर 2018 के लिए दाखिला प्रतिशत केवल 79 प्रतिशत था। यह देखा गया था कि जीएसटीआर-3बी रिटर्नों को 63 प्रतिशत करदाताओं द्वारा औसतन देय तिथि के भीतर दाखिल किया जा रहा था और 20 प्रतिशत ने नियत तिथि के बाद रिटर्नों को दाखिल किया। अप्रैल से दिसम्बर 2018 के दौरान नियत तारीख तक दाखिल जीएसटीआर-3बी रिटर्नों का प्रतिशत 59 से 68 तक की रेंज से कम प्रतिशत पर रहा था। इस प्रकार, जबकि यह उम्मीद थी कि अनुपालन में सुधार होगा क्योंकि प्रणाली समय बीतने के साथ स्थिर हो जाएगी, यह देखा गया कि नियत तारीख तक जीएसटीआर-3बी के दाखिल करने में कोई सुधार नहीं हुआ था।

चार्ट सं. 6: अप्रैल से दिसम्बर 2018 के लिए जीएसटीआर-1 और 3बी दाखिल करना

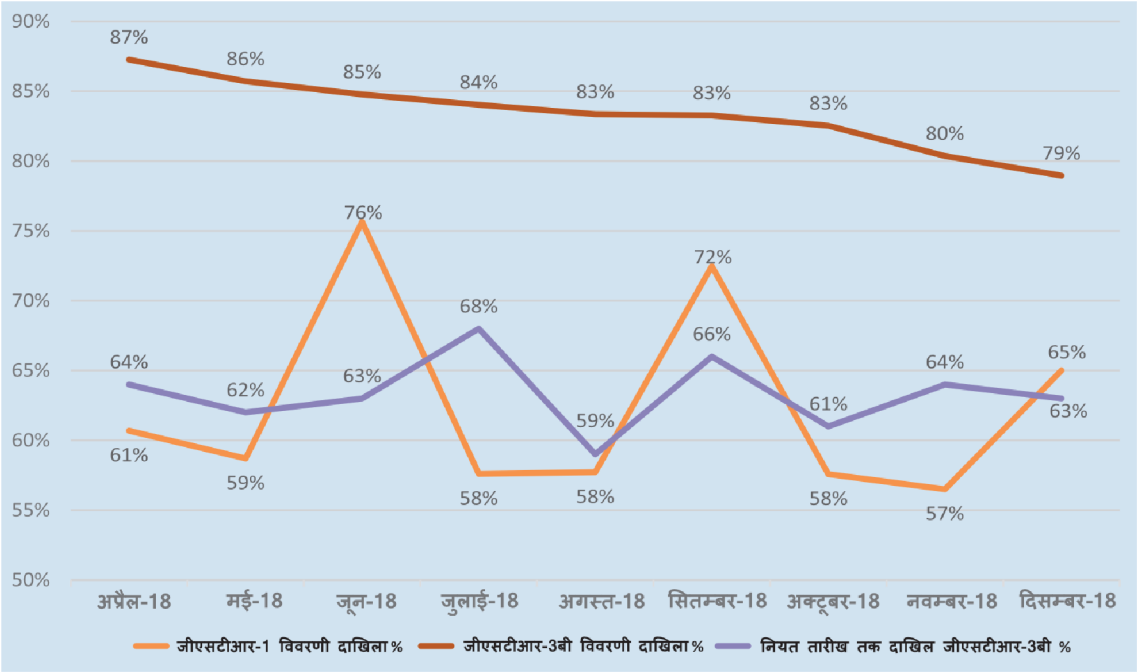

स्रोत: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीएन रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त किए गए सांख्यिकीय आंकड़े

- अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान जीएसटीआर-3बी रिटर्नों के अनुरूप दाखिला की तुलना में जीएसटीआर-1 रिटर्नों का दाखिला प्रतिशत शुरू से अन्त तक कम थी। आईटीसी के दावों के साथ रिर्टन दाखिल करने के परिणामस्वरूप जीएसटीआर-3 बी का परिचय हुआ जिसे सत्यापित नहीं किया जा सकता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जीएसटीआर-1 का भी दाखिला खरिज हो गया।
- विवरणी तंत्र में किए गए बदलावों के साथ, जीएसटीआर-1 एकमात्र विवरणी रहा है जो बीजक स्तर का विवरण प्रदान करेगा। इसके अलावा, जीएसटीआर-1 में आपूर्ति की गई जीएसटीआईएन-वार विवरण शामिल हैं, और इसलिए विभिन्न जीएसटीआर-1 से विवरणों को सम्मिलित करके, करदाताओं की एक रूपरेखा तैयार करना संभव होगा, जिनका उपयोग कर जीएसटी के तहत गैर-पंजीकृत या अपने कुल व्यापार की अंडर-रिपोर्टिंग करने वाले योग्य व्यापार को पहचाना जा सकता है।

जीएसटीआर-3बी केवल एक सारांश विवरणी है, जीएसटीआर-1 की शॉर्ट- दाखिला में अंतर्निहित है कि कर विभागों में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए बीजक स्तर का पूर्ण विवरण नहीं हैं जिसका उपयोग जीएसटीआर-3बी में दिए गए विवरणों को सत्यापित करने या कुल व्यापार को प्राप्त

करने में किया जा सकता है। जबसे जीएसटीआर-1 की दाखिला अनिवार्य हुई है, कम-दाखिला चिंता का क्षेत्र है और समाधान करने की आवश्यकता है।

- दिलचस्प है कि प्रत्येक तिमाही की समाप्ति में जीएसटीआर-1 दाखिला की प्रतिशतता मासिक दाखिला प्रतिशत से अधिक थी। जैसा कि तालिका संख्या 7 में देखा जा सकता है कि अप्रैल और मई 2018 के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने के कारण क्रमश: 45 लाख और 47 लाख करदाताओं के प्रति, केवल 27 लाख करदाताओं ने इन रिटर्नों को दाखिल किया। लेकिन जून महीने के लिए जिसमें ₹ 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं के विवरणी फाइल करने के लिए बकाया थे (अर्थात् तिमाही विवरणी), जीएसटीआर-1 फाइल करने के कारण कुल करदाता बढ़कर 93 लाख हो गए, जिसके प्रति 70 लाख लोगों द्वारा जीएसटीआर-1 दाखिल किया गया था। ऐसी प्रवृत्ति अगली दो तिमाहियों में भी देखी जा सकती थी।

जीएसटीआर-1 का दाखिला दरों में तिमाही में हुई बढ़ोतरी का कारण ये भी हो एकता है कि (i) ₹ 1.5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों की तुलना में छोटे करदाताओं ने जीएसटीआर-1 दाखिला का बेहतर अनुपालन किया है या (ii) ₹ 1.5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों के मासिक रिटर्नों के बजाय तिमाही विवरणी दाखिला करना है।

- मंत्रालय से (अप्रैल 2019) इस प्रवृत्ति के कारणों की जांच करने का अनुरोध किया और उन करदाताओं के ब्रेक-अप को प्रदान करने के लिए कहा जिसको ₹ 1.5 करोड़ से ऊपर एवं नीचे के टर्नओवर के साथ जीएसटीआर-1 दाखिल करना था, जिन्होंने देय तिथि तक और 31 दिसम्बर 2018 तक रिटर्नों को दाखिल किया। जवाब प्रतीक्षित था (जून 2019)।

2.3.2 जीएसटीआर-1 और 3बी का राज्यानुसार दाखिला पैटर्न

चार्ट सं. 7 दिसम्बर 2018 के लिए जीएसटीआर-1 और 3बी का राज्यानुसार दाखिला पैटर्न

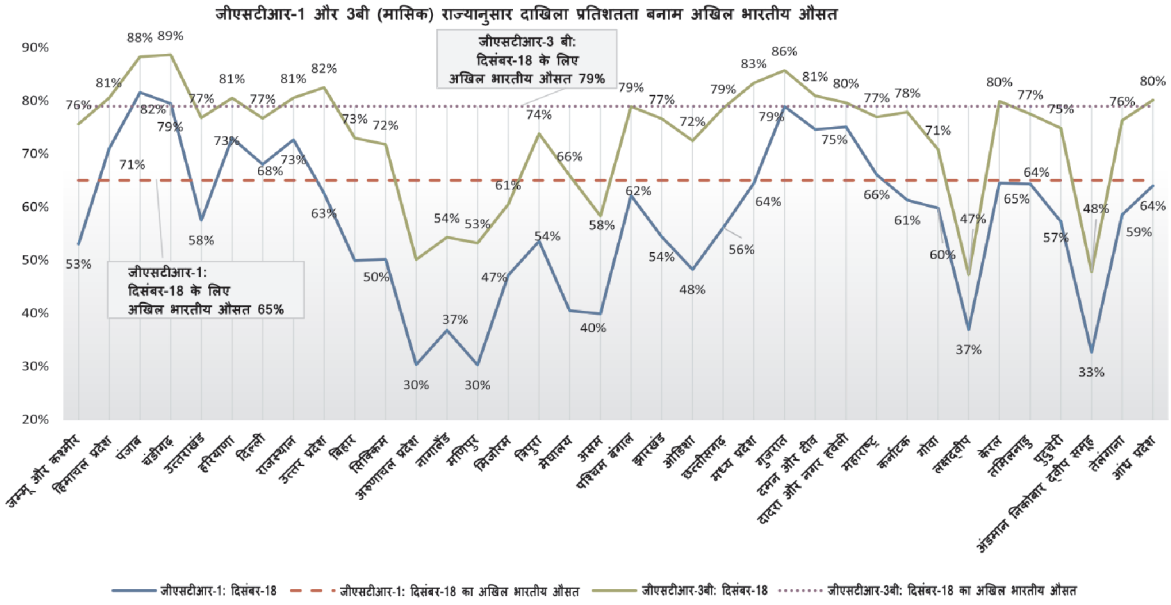

स्रोत: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीएन रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त किए गए सांख्यिकीय आंकड़े

देश भर में जीएसटीआर-1 की दाखिला या राष्ट्रीय औसत (दाखिल किए जाने के लिए देय रिटर्नों की प्रतिशतता के रूप में भरे गए रिटर्नों) दिसम्बर 2018 के महीने के लिए 65 प्रतिशत था। पंजाब में सबसे ज्यादा दाखिला देखे गये (82 प्रतिशत), उसके बाद गुजरात और केन्द्र शासित प्रदेश चंड़ीगढ़ में देखे गये (79 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी के राज्यों में, जीएसटीआर-1 का दाखिला ओड़ीसा (48 प्रतिशत), बिहार (50 प्रतिशत), झारखंड (54 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (56 प्रतिशत), तेलंगाना (59 प्रतिशत), गोवा (60 प्रतिशत), कर्नाटक (61 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (62 प्रतिशत) में अखिल भारतीय औसत से कम थे। केन्द्रशासित प्रदेशों में, चंड़ीगढ़ में सबसे ज्यादा दाखिला 79 प्रतिशत उसके बाद दमन एवं दीव और दादरा तथा नगर हवेली (75 प्रतिशत) में थे, जबकि पुदुच्चेरी (57 प्रतिशत) में राष्ट्रीय औसत से नीचे दाखिला दर दर्ज की गई।

देश भर में जीएसटीआर-3बी का दाखिला का राष्ट्रीय औसत 79 प्रतिशत है। केन्द्र शासित प्रदेश चंड़ीगढ़ (89 प्रतिशत) में सबसे ज्यादा दाखिला, उसके बाद पंजाब (88 प्रतिशत), गुजरात (86 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (83 प्रतिशत) में देखा गया था। सामान्य श्रेणी के अधिकतर, राज्यों में जीएसटीआर-3बी का दाखिला की दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर या लगभग समान थी।

मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या जीएसटीआर-1 के इतने कम विवरणी दाखिलों के कारणों का विश्लेषण किया गया है और इस तरह के विश्लेषण के आधार पर कोई कार्रवाई की गई और जवाब प्रतीक्षित था (जून 2019)।

2.3.3 जीएसटीआर-4 का दाखिला

जीएसटीआर-4 का दाखिला की प्रवृतियां, अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि के लिए 28 फरवरी 2019 तक कंपोजिशन द्वारा दाखिल एक तिमाही विवरणी को नीचे चार्ट सं.8 में दिया गया है (**परिशिष्ट-IV)** में पत्र अनुरूपी सांख्यिकीय विवरण)।

चार्ट सं. 8: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीआर-4 का दाखिला

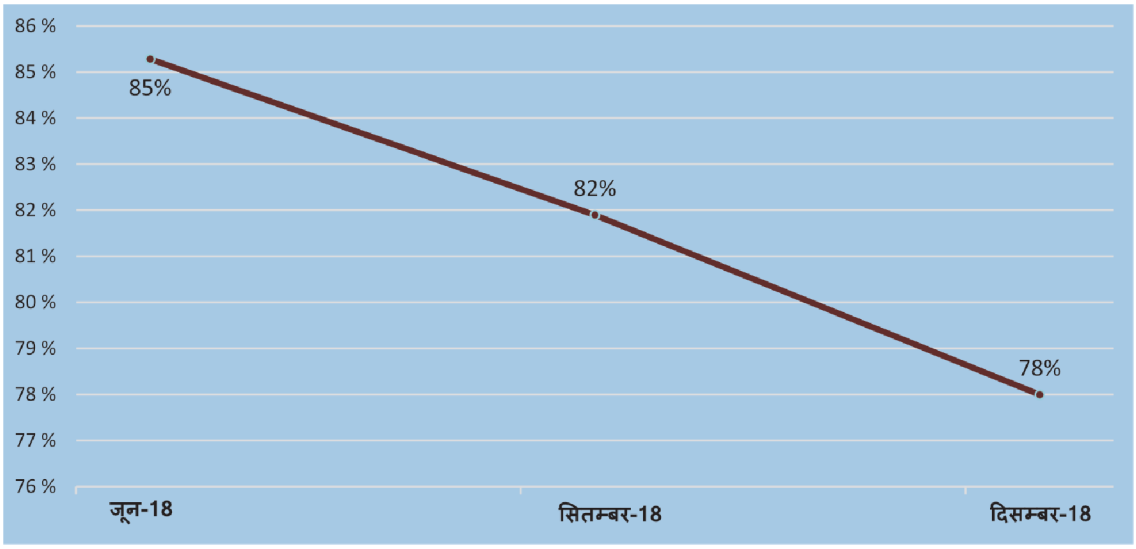

स्रोत: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीएन रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त किए गए सांख्यिकीय आंकड़े

जबकि कंपोजिशन द्वारा विवरणी दाखिला करना सामान्य करदाताओं (अर्थात जीएसटीआर-1) की विवरणी दाखिला दर से बेहतर प्रतीत होता है और लगभग समान रूप से सामान्य करदाताओं द्वारा सारांश विवरणी (अर्थात जीएसटीआर-3बी) के दाखिलों के साथ, मंत्रालय को जीएसटीआर-4 के दाखिलों में गिरावट के कारणों की जांच करना अपेक्षित था।

दिसम्बर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए जीएसटीआर-4 की राज्यानुसार दाखिला दर, 28 फरवरी 2019 तक नीचे दिए गए चार्ट सं. 9 में दी गई है:-

चार्ट सं. 9: दिसम्बर 2018 के लिए जीएसटीआर-4 की राज्यानुसार दाखिला

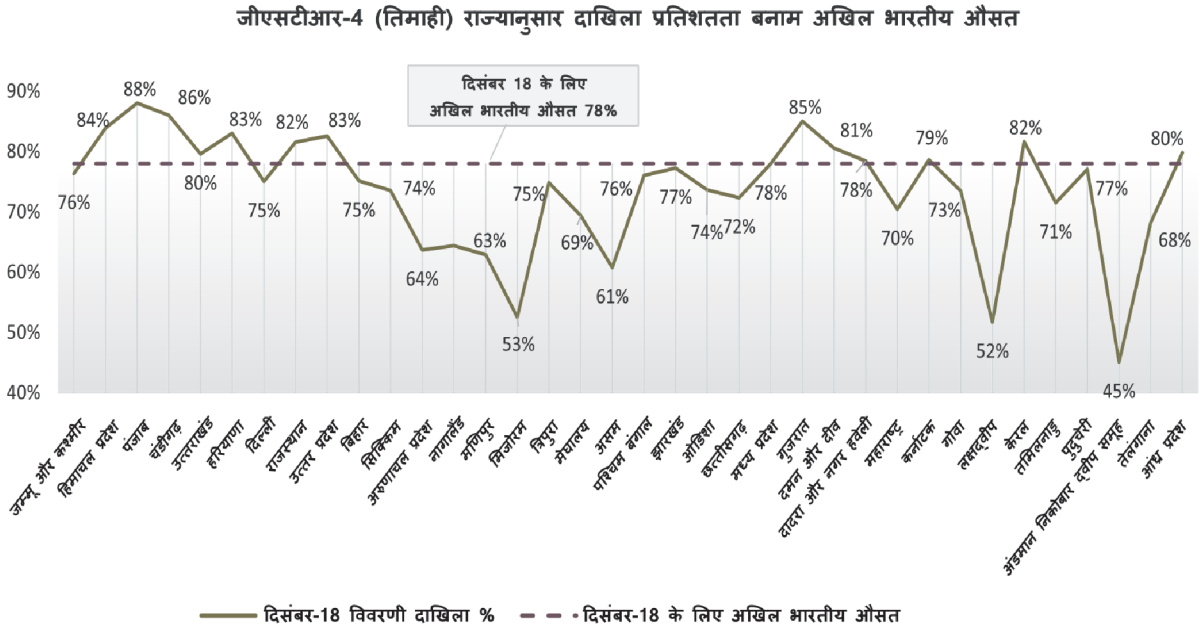

स्रोत: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीएन रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त किए गए सांख्यिकीय आंकड़े

जीएसटीआर-4 का सबसे अधिक दाखिला पंजाब (88 प्रतिशत) उसके बाद केन्द्र शासित प्रदेश चंड़ीगढ़ (86 प्रतिशत), गुजरात (85 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (84 प्रतिशत) में देखा गया था। सामान्य श्रेणी के राज्यों में, तेलंगाना (68 प्रतिशत), महाराष्ट्र (70 प्रतिशत) और तमिलनाडु (71 प्रतिशत) का दाखिला दरे 78 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम था जबकि अधिकांश विशेष श्रेणी के राज्यों में जीएसटीआर-4 की दाखिला राष्ट्रीय औसत से कम थी, जम्मू एवं कश्मीर (76 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (84 प्रतिशत) और उत्तराखंड (80 प्रतिशत) आदि में दाखिलों की दरे राष्ट्रीय औसत में ऊपर दर्ज की गई।

2.3.4 जीएसटीआर-5, 5ए और 6

जीएसटीआर-5 एक मासिक विवरणी है जो गैर-निवासी कर दाताओं/ आकस्मिक कर दाताओं द्वारा दाखिल किया जाता है। भारत में गैर-कर योग्य व्यक्ति को भारत के बाहर से ऑन लाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सेवाएं (ओआईडीएआर) प्रदान करने वालों द्वारा जीएसटीआर-5 दायर किया जाना चाहिए। इनपुट सेवा वितरक द्वारा जीएसटीआर-6 दायर किया जाता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्राप्ति और वितरण का विवरण देता है।

अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि के लिए 28 फरवरी 2019 को जीएसटीआर-5, 5ए और 6 में दाखिलों की प्रवृत्तियों को नीचे चार्ट सं.10 में दिया गया है (**परिशिष्ट-II** में अनुरूपी सांख्यिकीय विवरण)।

चार्ट सं.10: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीआर-5, 5ए और 6 का दाखिला

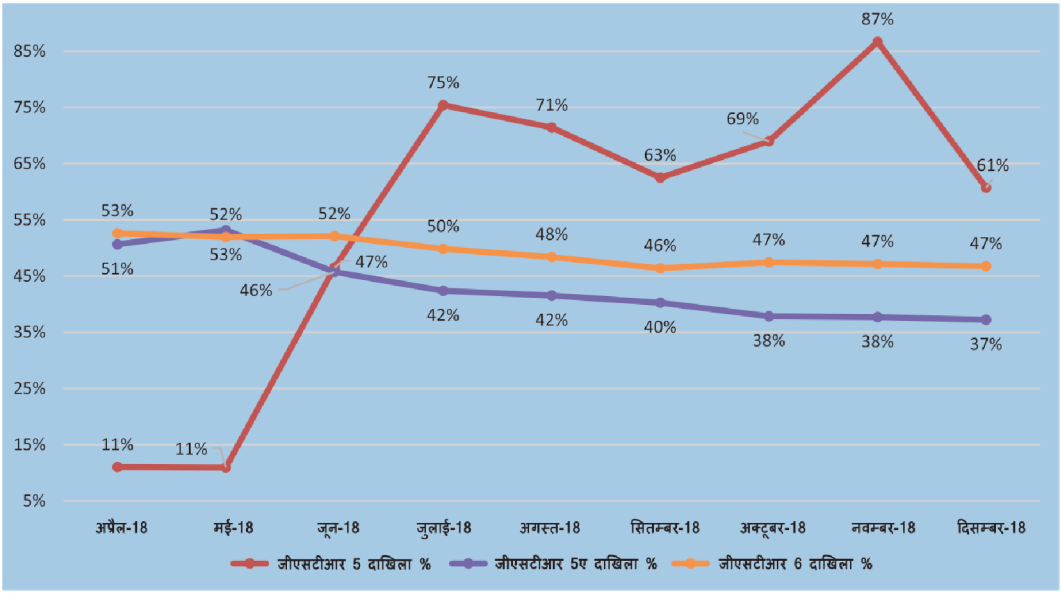

स्रोत: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीएन प्रतिवेदनों के माध्यम से प्राप्त किए गए सांख्यिकीय आंकड़े

जैसा कि ऊपर के लेखाचित्र से देखा जा सकता है, ओआईडीएआर सेवा प्रदाताओं द्वारा जीएसटीआर-5ए के दाखिले ने केवल अप्रैल और मई 2018 में 50 प्रतिशत को पार किया है और जून 2018 से इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। यह देखते हुए कि केन्द्रीय कर, बेंगलुरू (पश्चिम) के प्रधान आयुक्त द्वारा केन्द्र में सभी ओआईडीएआर करदाताओं के प्रशासन के लिए प्रावधानों के साथ इस श्रेणी के लिए एक अलग पंजीकरण श्रेणी और विवरणी फॉर्म निर्धारित किया गया है, मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि यदि इस तरह के कम विवरणी दाखिलों के कारणों की इस श्रेणी का विश्लेषण किया है तो इस तरह के विश्लेषण के आधार पर की गई कार्रवाई की सूचना दें। इसी प्रकार आईएसडी द्वारा जीएसटीआर-6 के दाखिले के संबंध में विश्लेषण या कार्रवाई की गई, जो लगभग 50 प्रतिशत था, जिसे मंत्रालय से भी मांगा गया है। जवाब प्रतीक्षित था (जून 2019)।

2.4 निष्कर्ष

राजस्व विश्लेषण

- अप्रत्यक्ष कर की वृद्धि 2016-17 से 2017-18 से 5.80 प्रतिशत कम हो गई थी जबकि यह वृद्धि दर 2016-17 में 21.33 प्रतिशत थी।

- जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, वस्तुओं और सेवाओं (पेट्रोलियम और तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बिना) पर केन्द्र के राजस्व में 2016-17 में शामिल करों के राजस्व की तुलना में 2017-18 में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
- भारत सरकार ने वित्त आयोग के फार्मूले के अनुसार राज्यों को वर्ष के अन्त में आईजीएसटी विचलन का सहारा लिया, जो भारत के संविधान और आईजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। इससे राज्यों को निधियों के वितरण का प्रभाव भी पड़ता है जो "प्लेस ऑफ सप्लाई" की अवधारणा के बजाय पूरी तरह से अलग आधार पर है जैसाकि आईजीएसटी अधिनियम में परिकल्पित है।
- 2017-18 के दौरान लोक लेखा से जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के ₹ 6,466 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ।

विवरणी दाखिल करना

- यद्यपि यह उम्मीद थी कि जैसे ही प्रणाली स्थिर होगी अनुपालन में सुधार होगा, सभी विवरणी दाखिल किए जा रहे हैं (जीएसटीआर-1, 3बी, 4, 5ए और 6) ने अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक दाखिले की गिरावट को दर्शाया है।
- जीएसटीआर-1 रिटर्नों की दाखिला प्रतिशतता जीएसटीआर-3बी विवरणी के अनुरूप दाखिलों की तुलना में हमेशा से कम थी। जीएसटीआर-3बी आरंभ करने के परिणामस्वरूप आईटीसी दावों के साथ रिटर्नो का दाखिला हुई जिसे सत्यापित किया जा सकता था तथा यह समान जीएसटीआर-I के दाखिलों का हतोत्साहन प्रतीत होता है। चूंकि जीएसटीआर-I का दाखिला अनिवार्य है अत: कम-दाखिला चिंता का विषय है तथा इसका समाधान करने की आवश्यकता है।
- जीएसटीआर3-बी केवल एक सारांश विवरणी है, जीएसटीआर 1-के कम-दाखिला का अर्थ है कि कर विभागों के पास आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए बीजक स्तर का पूरा विवरण नहीं है, जिसका उपयोग जीएसटीआर3-बी में दिए गए विवरणों को सत्यापित करने या टर्नओवर तक पहुँचने के लिए किया जा सकता है।